

भारत में सार्वभौमिक शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का विश्लेषण

Manju Gupta

Research Scholar

University of Technology, Jaipur

Dr. Jai prakash Tiwari

Supervisor

University of Technology, Jaipur

DECLARATION: I ASAN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BYME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/ OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETED DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

सार:

भारत में आजकल, दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है जो अधिक सीखना चाहते हैं और अपने कौशल में सुधार करना चाहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति शिक्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए सभी राष्ट्रों के नागरिकों को इसे अधिक महत्व देना चाहिए। वर्तमान शोध में, हम दूरस्थ शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों, भारतीय शिक्षा प्रणाली पर दूरस्थ शिक्षा के प्रभाव, दूरस्थ शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और दूरस्थ शिक्षा की प्रभावकारिता की जाँच करते हैं।

कीवर्ड: भारत, सार्वभौमिक, शिक्षा, कार्यान्वयन, दूरस्थ

1. परिचय

आज की दुनिया में, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर (ओडीई) रही है। भारत में एक विकसित उच्च शिक्षा प्रणाली है, जो मानव रचनात्मक और बौद्धिक प्रयासों के लगभग सभी पहलुओं में शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है। संस्थागत ढांचे में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालयों के रूप में राज्य विधानमंडल और डीम्ड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज, दोनों सरकारी सहायता प्राप्त हैं। और गैर सहायता प्राप्त, 31 मार्च 2016 तक, भारत में 749 विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान जिनमें 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 345 राज्य विश्वविद्यालय, 123 डीम्ड विश्वविद्यालय और 235 निजी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं, एक ऐसा दर्जा है जिसे सार्वजनिक उच्चतर को प्रदान किया जा सकता है। संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा संस्थान 23 अप्रैल 2015 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस श्रेणी के तहत 74 संस्थानों को सूचीबद्ध किया है। वर्तमान में एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, और 16 सितंबर 2016 तक 98 निदेशालय संबंधित राज्य अनुदान द (डीडीई/डीईआई) वारा स्थापित हैं, जो एकलमोड संस्थान हैं-, यानी वे केवल दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं।[1-2]

2. दूरस्थ शिक्षा का इतिहास

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुक्त अधिगम प्रणाली की शुरुआत विद्यालय स्तर पर हुई। पहले तीन मुक्त शिक्षण संस्थान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैंड में क्रमशः 1916, 1919 और 1922 में स्थापित किए गए थे। 1969 में यूनाइटेड किंगडम में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना ने कई देशों को नई अवधारणा और उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और अभिनव बनाने की इसकी क्षमता पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत उन देशों में से एक था जिसने सत्र के दशक की शुरुआत में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना तलाशी थी। इसने सत्र के दशक के मध्य में खुली शिक्षा नीतियों को अपनाने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों को प्रभावित किया।[3-4]

3. दूरस्थ शिक्षा

दूरस्थ शिक्षा, जिसे दूरस्थ शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, उन छात्रों की शिक्षा है जो हमेशा एक स्कूल में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं या जहां शिक्षार्थी और शिक्षक समय और दूरी दोनों में अलग होते हैं। परंपरागत रूप से, इसमें आमतौर पर पत्राचार पाठ्यक्रम शामिल होते थे जिसमें छात्र मेल के माध्यम से स्कूल के साथ संपर्क करता था। दूरस्थ शिक्षा एक प्रौद्योगिकी-मध्यस्थ साधन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ विकसित हुई है। आज, इसमें आम तौर पर ऑनलाइन शिक्षा शामिल है, और सीखने की प्रक्रिया आमतौर पर किसी प्रकार की तकनीक

द्वारा मध्यस्थता की जाती है। एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पूरी तरह से दूरस्थ शिक्षा हो सकता है, या दूरस्थ शिक्षा और पारंपरिक कक्षा निर्देश (जिसे हाइब्रिड या मिश्रित कहा जाता है) का संयोजन हो सकता है। अन्य तौर-तरीकों में एक पूरक आभासी वातावरण के साथ दूरस्थ शिक्षा या एक आभासी वातावरण (ई-लर्निंग) में शिक्षण शामिल है।[5-6]

4. भारत में शिक्षा प्रणाली

i. प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा मध्य और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के साथ 6-14 वर्ष से शुरू होती है। स्कूली शिक्षा राजकीय और निजी स्कूलों में दी जाती है, हालांकि, निजी स्कूलों में अक्सर सरकारी स्कूलों की तुलना में अच्छी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा होता है। भारत में शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के साथसाथ निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नियंत्रण और धन तीन स्तरों से आता है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। भारतीय संविधान, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहा है।[7]

ii. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा ग्रेड 9 में शुरू होती है और ग्रेड 12 तक चलती है। माध्यमिक स्तर को दो साल के चक्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे आमतौर पर निम्न माध्यमिक विद्यालय, या मानक 10वीं, और उच्चवर्ष माध्यमिक विद्यालय/, या मानक 12वीं कहा जाता है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा अभी भी मुफ्त है, हालांकि माध्यमिक स्तर पर निजी शिक्षा अधिक आम है। सार्वजनिक परीक्षाएं दोनों चक्रों के अंत में आयोजित की जाती हैं और क्रमशः ग्रेड 11 और विश्वविद्यालय स्तर के अध्ययन तक पहुंच प्रदान करती हैं। भारत में एक निम्न माध्यमिक विद्यालय के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा, एक वैकल्पिक और अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कार्यव्यावसायिक शिक्षा-पूर्व/, कला और शारीरिक शिक्षा सहित तीन भाषाएँ शामिल हैं।

iii. व्यावसायिक शिक्षा

युवा लोग जो तृतीयक शिक्षा पर नहीं जाना चाहते हैं, या जो माध्यमिक विद्यालय पूरा करने में विफल रहते हैं, वे अक्सर निजी स्वामित्व वाले व्यावसायिक स्कूलों में दाखिला लेते हैं जो केवल एक या केवल कुछ पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञ होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा अत्यधिक विशिष्ट नहीं है और बल्कि रोजगार के लिए लागू ज्ञान का एक व्यापक अवलोकन है। पेश किया गया पाठ्यक्रम एक भाषा पाठ्यक्रम, फाउंडेशन पाठ्यक्रम और ऐच्छिक से बना है, जिनमें से आधे ऐच्छिक व्यावहारिक हैं।[8]

iv. तृतीयक शिक्षा

1947 में अपनी स्थापना के बाद से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत है और बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित, शिक्षा नीति हमेशा विकासशील है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी प्रणालियों में से एक है। इन संस्थाओं के सामने प्रबंधन और नियमन की नई चुनौतियाँ भी हैं, जिन पर

गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और निजी क्षेत्र के संस्थानों में भी जो अब तेजी से बढ़ रहे हैं। नतीजतन, पूर्वस्वतंत्र भारत में स्थापित और बीसवीं - शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान काम कर रहे प्रबंधन के पुराने ढांचे को अब कठोर परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है।[9]

5. निष्कर्ष

स्कूल प्रणाली में अभी भी विकास के लिए बहुत जगह है, यह निष्कर्ष निकाला है। महिलाओं की दूरस्थ शिक्षा में उनकी व्यावसायिक सफलता और दूरस्थ शिक्षा की घटना के लिए एक प्रशंसनीय व्याख्या के रूप में महिलाओं की चेतना की मान्यता के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरुषों द्वारा विकसित दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत महिलाओं के अनुभवों का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। तेजी से महिलाओं से बने एक छात्र निकाय के लिए उपयुक्त सिद्धांत और व्यवहार विकसित करने के लिए, महिलाएं मूल रूप से प्राथमिक व्यक्ति हैं। इसके अलावा, विभिन्न कार्य समूहों के उत्तरदाताओं में, 40.0% नियोजित और 45.5% व्यवसायियों ने पत्राचार शिक्षा को प्राथमिकता दी, जबकि 33.9% नियोजित अध्ययन) और बेरोजगार उत्तरदाताओं ने एमओओसी को अपने पसंदीदा शैक् (अवकाश परषिक विकल्प के रूप में चुना।

6. संदर्भ:

1. भट्टाचार्य जोनाकी, (2016) हायर एजुकेशन इन इंडिया: रीसेंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स, रिसर्च जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइंसेज, वॉल्यूम। 4(1), 10-16

2. डॉ मुजीबुल हसन सिद्दीकी (2018) "दूरस्थ शिक्षा के लिए गैर-प्रिंट मीडिया की प्रभावशीलता", खंड: 1 | अंक: 5 | आईएसएसएन नंबर 2277 - 8179।
3. जोई एल. मूर (2016), केमिली डिक्सन-डीन और क्रिस्टा गैलेन "ई-लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, और दूरस्थ शिक्षा वातावरण: क्या वे वही हैं?", इंटरनेट और उच्च शिक्षा पीजी। संख्या 129-135।
4. पीटर डब्ल्यू ओल्सन, (2015) "दूरस्थ शिक्षा में महत्वपूर्ण सफलता कारक", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ केस मेथड रिसर्च एंड एप्लीकेशन (2005) Xvii, 2 © 2005 वाक्रा®। सर्वाधिकार सुरक्षित इस्सुन 1554-7752
5. समीर हिजाज़ी (2018) "इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी डिस्टेंस एजुकेशन", इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ़ ई-लर्निंग, वॉल्यूम 1 अंक 1, 35-44
6. एम. मोजम्मेल हक चौधरी (2015)। "बांग्लादेश के लिए मॉडलिंग ई-लर्निंग असिस्टेड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉल्यूम। 56.
7. टेलर, जेनेट ए और मोहर, जोन (2016)। दूर रहकर पढ़ने वाले गणित-चिंतित छात्रों के लिए गणित। जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंटल एजुकेशन, 25(1), पीपी 30-37।
8. लार्सन, मैथ्यू आर। और ब्रूनिंग, रोजर (2019)। एक सहयोगी उपग्रह-आधारित गणित पाठ्यक्रम की प्रतिभागी धारणाएँ। द अमेरिकन जर्नल ऑफ़ डिस्टेंस एजुकेशन, 10(1), पीपी 6-22।

9. डॉ. अजय कुमार अत्री (2020)। "डिस्टेंस एजुकेशन: प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस"
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिहेवियरल सोशल एंड मूवमेंट साइंसेज वॉल्यूम। 01, अंक-04
आईएसएन: 2277- 7547.

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by mean if any person having copyright issue or patent or anything other wise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me isnot correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed I website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me

Manju Gupta

Dr. Jai prakash Tiwari